50 लाख टन चीनी के एक्सपोर्ट टारगेट से चूक सकता है भारत

सितंबर में खत्म होने वाले मौजूदा सीजन में अभी तक सिर्फ 34 लाख टन चीनी का निर्यात हुआ है

[ऋतुराज तिवारी | नई दिल्ली]

चीनी के 50 लाख टन एक्सपोर्ट का टारगेट भारत चूक सकता है। 30 सितंबर को समाप्त हो रहे मौजूदा सीजन में अभी तक केवल 34 लाख टन का एक्सपोर्ट किया गया है। इंडस्ट्री के एक एक्सपर्ट ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया, 'इस सीजन में एक लाख टन और चीनी का निर्यात किया जा सकता है। इससे सरकार की ओर से तय किए गए कुल टारगेट का 70 पर्सेंट हासिल किया जाएगा। सरकार की ओर से दिए जा रहे इंसेंटिव के बावजूद ग्लोबल प्राइसेज का मुकाबला करने में मुश्किल हो रही है।'

डोमेस्टिक मार्केट में चीनी की सप्लाई बहुत अधिक बढ़ने के कारण सरकार ने एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए कुछ इंसेंटिव की पेशकश की थी। इनमें चीनी मिलों के लिए प्रति टन पर 1,000-3,000 रुपये की ट्रांसपोर्ट सब्सिडी शामिल थी। इंडस्ट्री ने आगामी सीजन में 70 लाख टन चीनी का निर्यात करने का लक्ष्य रखा है। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (इस्मा) के डायरेक्टर जनरल अबिनाश वर्मा ने बताया, 'मौजूदा सीजन में 20 लाख टन चीनी का ग्लोबल सरप्लस है और इस वजह से हम 50 लाख टन के एक्सपोर्ट का टारगेट पूरा नहीं कर सकते। हालांकि, अगले सीजन में डिमांड और सप्लाई में 40 लाख टन का अंतर होने की संभावना है। इससे एक्सपोर्ट करना फायदेमंद होगा। सप्लाई कम होने के पीछे भारत और पाकिस्तान में कम उत्पादन और ऑस्ट्रेलिया में सूखा पड़ना प्रमुख कारण हैं। हम अगले सीजन में 70 लाख टन का निर्यात कर सकते हैं।'

ट्रांसपोर्ट सब्सिडी

- डोमेस्टिक मार्केट में सप्लाई बढ़ने पर सरकार ने एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए चीनी मिलों को ₹1,000-3,000 प्रति टन की ट्रांसपोर्ट सब्सिडी की पेशकश की थी

इस्मा का अनुमान है कि 2019-20 में देश का चीनी उत्पादन 2.82 करोड़ टन के साथ तीन वर्ष के निचले स्तर पर आ सकता है। चीनी के बड़े उत्पादन क्षेत्रों में सूखा मौसम होना इसका कारण है। वर्मा ने कहा कि इंडस्ट्री को अगले सीजन में चीनी के निर्यात के लिए सरकार से मदद की जरूरत होगी। उनका कहना था, 'सरकार को इंसेंटिव जारी रखने चाहिए, लेकिन उसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइजेशन (WTO) के प्रोविजंस का पालन भी करने की जरूरत है। WTO के नियमों के तहत सरकार डायरेक्ट एक्सपोर्ट सब्सिडी दे सकती है।'

दुनिया में चीनी के बड़े उत्पादकों ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया ने एक्सपोर्ट के लिए सब्सिडी उपलब्ध कराने और ग्लोबल शुगर मार्केट में स्थिति खराब करने को लेकर भारत के खिलाफ WTO में शिकायतें दर्ज कराई थीं।

Economic Times

9/8/19